

ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता

¹शिव कुमार कंवर, ²डॉ.ए.राजशेखर

¹शोध छात्र, ²प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

^{1,2}भूगोल विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, नवा रायपूर, छत्तीसगढ़ – 492101

ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाओं की पहुँच विविध रूपों में है, और उनका लाभ अलग-अलग स्तर पर लोगों को मिल रहा है। KCC ग्रामीण कृषि वित्त का प्रमुख आधार है; SHG ऋण महिलाओं और कमजोर वर्गों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ा रहा है; मुद्रा योजना ग्रामीण उद्यमिता का नया मार्ग बना रही है; जबकि जनधन योजना वित्तीय समावेशन की नींव को मजबूत करती है। यह तालिका स्पष्ट संकेत देती है कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सरकारी योजनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनकी पहुँच और लाभ ग्रहण करने की क्षमता विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में भिन्न है। योजनाओं की प्रभावशीलता तभी अधिक बढ़ेगी जब जागरूकता, प्रशिक्षण, बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और सामाजिक समर्थन संरचना और मजबूत हो सकेगी।

सारणी क्रमांक 1.1

किन योजनाओं का लाभ आपने प्राप्त किया है?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	300	60.0
स्वयं सहायता समूह (SHG) लोन	146	29.0
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	49	9.8
जनधन योजना	51	1.2

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त

सारणी क्रमांक 1.1 ग्रामीण क्षेत्र के उन प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करती है, जिनका लाभ उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त किया गया है। तालिका में चार योजनाएँ, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा जनधन योजनाकृ शामिल हैं। इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत ग्रामीण आर्थिक विकास में इन कार्यक्रमों की पहुँच एवं प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।

सारणी के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सबसे अधिक लोकप्रिय एवं व्यापक रूप से लाभान्वित योजना है, जिससे कुल 300 उत्तरदाता लाभान्वित हुए हैं, जो कुल उत्तरदाताओं का 60 प्रतिशत है। यह उच्च प्रतिशत इस बात का संकेत है कि कृषि अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए सुलभ एवं उपयोगी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को आसान ब्याज दरों पर ऋण मिलता है, जिससे वे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पशुपालन, सिंचाई तथा फसल प्रबंधन में खर्च कर पाते हैं। KCC का उच्च लाभार्थी प्रतिशत ग्रामीण वित्तीय समावेशन एवं कृषि क्षेत्र की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

सारणी में दूसरी प्रमुख योजना स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण है, जिसके 148 लाभार्थी दर्ज हैं। जो कुल उत्तरदाताओं का 29 प्रतिशत है। SHG ऋण महिला सशक्तिकरण, सूक्ष्म उद्यमिता तथा आय-सृजन के अवसरों को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में SHG न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक एकजुटता, नेतृत्व विकास और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा देते हैं। 29 प्रतिशत लाभार्थी यह संकेत देते हैं कि ग्रामीण

महिलाएँ आजीविका गतिविधियों, छोटे व्यवसायों, कृषि-आधारित उद्यमों और घरेलू उद्योगों में सक्रिय रूप से जुड़ रही हैं। यह ग्रामीण विकास की एक सकारात्मक दिशा है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 49 लाभार्थी (9.8 प्रतिशत) मिले हैं, जो ग्रामीण युवाओं और छोटे उद्यमियों में बढ़ती उद्यमिता का संकेत है। हालांकि प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी व्यवसाय, दुकानें, पशुपालन, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोटर मरम्मत जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण लिए जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में उद्यमिता का विकास पारंपरिक कृषि-निर्भरता को कम करने और बहुविध आय-स्रोत उत्पन्न करने में सहायक होता है। जनधन योजना के 51 लाभार्थी (1.2 प्रतिशत) दर्शाए गए हैं। यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है, जबकि जनधन योजना देशव्यापी स्तर पर सफल मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में कम प्रतिशत का कारण यह हो सकता है कि उत्तरदाताओं के अधिकांश परिवार पहले से बैंक खातों का उपयोग कर रहे थे या इस सर्वेक्षण में बैंक खाते को 'लाभ' के रूप में नहीं माना गया। फिर भी, जनधन योजना वित्तीय समावेशन की आधारशिला है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच, सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ, बीमा कवरेज और बचत की संस्कृति विकसित हुई है।

सारणी क्रमांक 1.2 क्या बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान था?

बहुत आसान	350	70.0
आसान	125	25.0
कठिन	13	2.6
बहुत कठिन	12	2.4

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त

सारणी क्रमांक 1.2 ग्रामीण क्षेत्र में बैंक ऋण की उपलब्धता तथा उसकी सुगमता के प्रति उत्तरदाताओं की धारणा को दर्शाती है। तालिका में चार श्रेणियों कृ“बहुत आसान”, “आसान”, “कठिन”, और “बहुत कठिन”कृके आधार पर ग्रामीणों के अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है। यह तालिका ग्रामीण वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं की पहुँच, तथा ऋण प्राप्ति की वास्तविक स्थितियों का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य देती है।

सारणी के अनुसार, 350 उत्तरदाताओं (70%) ने कहा कि बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत आसान था। यह एक सकारात्मक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार तथा ऋण वितरण प्रक्रिया में सुधार सफल रहा है। यह स्थिति प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकिंग, और ग्रामीण शाखाओं के बढ़ते नेटवर्क के कारण संभव हुई है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान प्रणाली, आधार आधारित ई-केवाईसी, और सरल दस्तावेजीकरण ने भी ऋण प्राप्ति को सहज बनाया है। यह उच्च प्रतिशत ग्रामीण विकास की दिशा में बैंकिंग प्रणाली की सक्रिय भूमिका की पुष्टि करता है।

दूसरी श्रेणी में, 125 उत्तरदाताओं (25%) ने ऋण प्राप्ति को आसान बताया। यह दर्शाता है कि ग्रामीण समुदाय का एक बड़ा भाग बैंकिंग प्रक्रिया से संतुष्ट है, किंतु कुछ औपचारिकताओं, जैसे दस्तावेजी प्रक्रिया, गारंटी व्यवस्था, या बैंक कर्मचारियों से संवाद, में उन्हें मध्यम स्तर की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी, इन उत्तरदाताओं की राय

बताती है कि बैंक और ग्राहक के बीच भरोसा बढ़ रहा है तथा ग्रामीण नागरिक औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने लगे हैं।

तीसरी श्रेणी में, 13 उत्तरदाता (2.6%) ने ऋण प्राप्ति को कठिन बताया। यह प्रतिशत भले ही कम है, परंतु यह दर्शाता है कि ग्रामीण समाज के कुछ वर्ग अभी भी आवश्यक दस्तावेज न होने, कम ऋण इतिहास, सीमित जमानत क्षमता, या बैंक कर्मचारियों की उदासीनता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस समूह को अधिक वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी, और सहायता की आवश्यकता है, ताकि वे भी औपचारिक ऋण व्यवस्था से सहज रूप से लाभ उठा सकें।

अंतिम श्रेणी में, 12 उत्तरदाता (2.4%) ने ऋण प्राप्ति को बहुत कठिन माना। यह समूह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। इनमें असंगठित वर्ग, सीमांत किसान, महिला उद्यमी, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, तथा ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज या गारंटी उपलब्ध नहीं होती। यह प्रतिशत यह इंगित करता है कि वित्तीय समावेशन अभी भी पूरी तरह संतुलित नहीं है और ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में कुछ संरचनात्मक बाधाएँ मौजूद हैं।

सारणी क्रमांक 4.7 का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में बैंक ऋण एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो कृषि, पशुपालन, छोटे व्यवसाय, स्व-रोजगार, और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अधिकांश उत्तरदाता ऋण प्रक्रिया को सरल मानते हैं, जो ग्रामीण

अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ, वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम, और ग्रामीण बैंकिंग ढांचा सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं।

हालाँकि, 'कठिन' और 'बहुत कठिन' श्रेणी में आने वाले उत्तरदाताओं की समस्याएँ यह संकेत देती हैं कि वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से सीमांत किसानों, महिलाओं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण प्रक्रिया को और सरल, पारदर्शी तथा सहायक बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. अर्जुन कुमार मौर्य, जय शंकर शुक्ल. ग्रामीण विकास में कौशल विकास की भूमिका एवं अपेक्षाओं का अवलोकनार्थ अध्ययन (फैजाबाद (अयोध्या) जिला के विशेष संदर्भ में). *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*- 2022 (2022; 10(4):145-2.
2. रवि प्रकाश पाण्डेय, रामजी बंशकार. भारतीय ग्रामीण विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान—एक आर्थिक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में). *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*. 2024; 12(1):57-6. doi: 10.52711/2454-2687.2024.00011 <https://ijrrsonline.in/AbstractView.aspx?PID=2024-12-1-11>
3. Gautam, Rahul & Kanoujiya, Jagjeevan. (2022). Role of Regional Rural Banks in Rural Development and Its Influences on Digital Literacy in India. 5. 92-101.
4. Mr. Srinivasa.K.1.,& Challakumar J.A. Arul (2022) Regional Rural Banks and Rural Economic Development August 2022, *IJIRT* ,Volume 9 Issue 3 | ISSN: 2349-6002
5. Dhanda, Rakshanda. (2020). A Study on Role of STATE BANK OF INDIA in Financial Inclusion.